

उत्तराखण्ड के 85 फीसदी ज़िले चरम बाढ़ से प्रभावित : सीईईडब्ल्यू

उत्तराखण्ड में बाढ़ की घटनाएं 1970 के बाद चार गुना बढ़ी हैं।

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021: उत्तराखण्ड के 85 फीसदी ज़िले जहां नब्बे लाख लोग रहते हैं, चरम बाढ़ एवं इससे संबंधित घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं, काउन्सिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेन्ट एण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा जारी एक स्वतन्त्र विश्लेषण के तहत आज यह जानकारी दी गई। 1970 के बाद से उत्तराखण्ड में चरम बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता चार गुना बढ़ गई है। इस अवधि में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं जैसे भूस्खलन, बादल फटना, ग्लेशियर फटना आदि में भी चार गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जान-माल को नुकसान पहुंचा है। राज्य के चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी ज़िले चरम बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।

अबिनाश मोहंती, प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू ने कहा, “हाल ही में उत्तराखण्ड में आई विनाशकारी बाढ़ इस बात का प्रमाण है कि जलवायु संकट की अब और अनदेखी नहीं की जा सकती। पिछले 20 सालों में उत्तराखण्ड ने 50,000 हेक्टेयर वनों को खोया है, जिसके चलते क्षेत्र में सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में चरम जलवायु घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ज़मीन-उपयोग आधारित वनों के पुनरुद्धार के द्वारा ही जलवायु के असंतुलन में सुधार लाया जा सकता है, इससे राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही बुनियादी सुविधाओं, निवेश और नीतियों के लिए क्लाइमेट प्रूफिंग पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अब यह विकल्प नहीं रहा, इस तरह की चरम घटनाओं को नियंत्रित करना राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन चुका है ताकि जान-माल को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।”

अरूणाभ घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईईडब्ल्यू ने कहा, “उत्तराखण्ड में आई आपदा ज़िला स्तर पर विस्तृत जलवायु जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर देती है। इसके अलावा चूंकि चरम जलवायु घटनाओं का सबसे ज़्यादा असर प्रभावित समुदायों पर पड़ता है, उन्हें जोखिम मूल्यांकन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। अंत में, चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए भारत को तुरंत राष्ट्रव्यापी और विकेन्द्रीकृत, संरचनात्मक, रियल-टाइम डिजिटल आपातकालीन निगरानी एवं प्रबन्धन प्रणाली का विकास करना होगा। साथ ही, बिज़नेस-एज़-यूज़युअल-डेवलपमेन्ट मॉडल का बिना सोचे समझे अनुकरण नहीं कर सकते। ये घटनाओं लोगों के जीवन और आजीविका पर भारी पड़ रही हैं, साथ ही इनसे बुनियादी सुविधाओं को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। भारत को आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु अनुकूल योजना तैयार करनी होगी।”

पिछले साल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हिंदु कुश हिमालय में 1951-2014 के दौरान तापमान में तकरीबन 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इसक चलते उत्तराखण्ड में सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियल बदलाव आए हैं। जिसकी वजह से बाढ़ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले साल में इसका असर राज्य में चल रही 32 बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर पड़ सकता है, ऐसी हर परियोजना की लागत रु 150 करोड़ से अधिक है।

चरम बाढ़ की घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ सीईईडब्ल्यू ने यह भी बताया कि उत्तराखण्ड में 1970 के बाद से सूखे के मामले भी दोगुना बढ़े हैं और राज्य के 69 फीसदी ज़िले इससे प्रभावित हैं। साथ ही पिछले दशक में अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ ज़िलों में बाढ़ और सूखे की घटनाएं एक साथ घटी हैं। यह नीति निर्माताओं एवं प्रतिक्रिया दलों के लिए जोखिम-मूल्यांकन के फैसलों को और भी मुश्किल बनाता है।

2015 में सीईईडब्ल्यू और अन्य विश्वस्तरीय साझेदारों द्वारा जलवायु जोखिम मूल्यांकन पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली सदी में गंगा बेसिन में बाढ़ की आवृत्ति छह गुना बढ़ी है। सीईईडब्ल्यू द्वारा 2020 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के मुताबिक भारत के 75 फीसदी ज़िले और आधी आबादी चरम जलवायु से प्रभावित हैं।

सीईईडब्ल्यू के बारे में

काउन्सिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेन्ट एण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) दक्षिणी एशिया का अग्रणी गैर-लाभ नीति अनुसंधान संस्थान है। काउन्सिल संसाधनों के उपयोग, पुनःउपयोग और दुरुपयोग के स्पष्टीकरण एवं इसमें बदलाव के लिए आंकड़ों, समेकित विश्लेषण और सामरिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करता है। काउन्सिल एक समेकित एवं अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण के ज़रिए वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए तत्पर है। संस्थान को अपने गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर गर्व है; इसके लिए यह सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के साथ साझेदारी करता है और बड़े पैमाने पर आम जनता के साथ सक्रिय है। 2021 में सीईईडब्ल्यू को एक बार फिर से 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडैक्स रिपोर्ट में दस श्रेणियों में शामिल किया गया। परिषद को निरंतर दुनिया के शीर्ष पायदान के जलवायु थिंक टैंक्स में शामिल किया गया है। अधिक अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो करें @CEEWIndia

Contact: RiddhimaSethi, riddhima.sethi@ceew.in

Mihir Shah, mihir.shah@ceew.in